मेवात की अनोखी पहल

हरियाणा

हरिकिशन शर्मा

योजनाएं बनाते वक्त सरकारी तंत्र भले ही स्थानीय लोगों की समझ का सहारा लेने से परहेज करे, लेकिन कई बार आम लोगों की सोच ऐसे कार्यक्रमों का रुख सफलता की ओर मोड़ सकती है। हरियाणा के मेवात जिले में कुछ ऐसा ही हुआ है। अल्पसंख्यक बहुल इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं खस्ताहाल हैं। इलाज के लिए लोग दूर-दूर तक भटकते हैं। लेकिन निराशा और बदहाली के बीच यहां एक पहल ऐसी हुई, जिसने न सिर्फ करोड़ों गरीबों के लिए उम्मीद जगाई है, बल्कि अब वह राज्य सरकार के लिए रोल मॉडल भी बन गई है। मेवात की महिलाओं की एक नसीहत से प्रेरित होकर शुरू की गई फ्री एंबुलेंस सेवा आज लोकप्रियता का पचरम लहरा रही है। इस एंबुलेंस की सफलता यह साबित करती है कि अगर सरकारी योजना बनाते समय जनता की राय भी ली जाए, तो योजनाएं न सिर्फ लोकप्रिय होंगी, बल्कि सार्थक भी हो सकेंगी।

मेवात जिले के घासेड़ा गांव से अक्तूबर, 2007 में मुफ्त एंबुलेंस सेवा शुरू हुई। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और बीपीएल परिवार के मरीजों को अस्पताल आने के लिए मुफ्त एंबुलेंस सुविधा मुहैया कराई जाती है। यह सेवा बस एक फोन

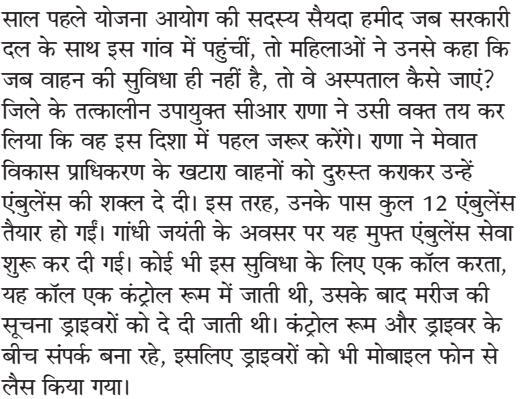

कॉल पर 24 घंटे उपलब्ध है। प्रशासन को यह सेवा शुरू करने की प्रेरणा जिले के टांई गांव की महिलाओं से मिली। करीब तीन साल पहले योजना आयोग की सदस्य सैयदा हमीद जब सरकारी दल के साथ इस गांव में पहुंचीं, तो महिलाओं ने उनसे कहा कि जब वाहन की सुविधा ही नहीं है, तो वे अस्पताल कैसे जाएं? जिले के तत्कालीन उपायुक्त सीआर राणा ने उसी वक्त तय कर लिया कि वह इस दिशा में पहल जरूर करेंगे। राणा ने मेवात विकास प्राधिकरण के खटारा वाहनों को दुरुस्त कराकर उन्हें एंबुलेंस की शक्ल दे दी। इस तरह, उनके पास कुल 12 एंबुलेंस तैयार हो गईं। गांधी जयंती के अवसर पर यह मुफ्त एंबुलेंस सेवा शुरू कर दी गई। कोई भी इस सुविधा के लिए एक कॉल करता, यह कॉल एक कंट्रोल रूम में जाती थी, उसके बाद मरीज की सूचना ड्राइवरों को दे दी जाती थी। कंट्रोल रूम और ड्राइवर के बीच संपर्क बना रहे, इसलिए ड्राइवरों को भी मोबाइल फोन से लैस किया गया।

यह एंबुलेंस सेवा इतनी कारगर साबित हुई है कि तीन साल में जिले में संस्थागत डिलीवरी में इससे भारी इजाफा हुआ है। वर्ष 2007 में जहां सिर्फ नौ फीसदी प्रसव अस्पतालों में हुआ था, वहीं 2009 में यह बढ़कर 18 फीसदी हो गया। अकेले नूंह के सिविल अस्पताल में वर्ष 2007 में जहां 207 बच्चों ने जन्म लिया, वहीं 2008 में यह 489 तक पहुंच गया। वर्ष 2010 में तो मार्च महीने तक ही 202 महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए अस्पतालों का दामन थामा। इस योजना की कामयाबी देखकर हरियाणा सरकार ने इसे पूरे प्रदेश के लिए रोल मॉडल बना लिया है। मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने नवंबर 2009 में इसे स्वास्थ्य वाहन योजना नाम देकर पूरे सूबे में लागू कर दिया। अब रेडक्रॉस इसका परिचालन कर रहा है।

गर्भवती महिलाओं, बीपीएल परिवारों, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए यह सेवा मुफ्त है, जबकि अन्य मरीजों से प्रति किलोमीटर सात रुपये की दर से भाड़ा लिया जाता है। अब केंद्र सरकार भी इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत पूरे देश में लागू करने की मंशा जता रही है। अगर ऐसा हुआ, तो यह कदम क्रांतिकारी होगा।

(लेखक अमर उजाला से जुड़े हैं)